जनसंख्या, मानवीय संसाधन और भारतीय अर्थव्यवस्था

Dr. Nishi Shukla

Assistant Professor

Department of Economics

Pt. D.D.U. Govt. Girls P.G. College Rajajipuram, Lucknow

जनसंख्या, मानवीय संसाधन और भारतीय अर्थव्यवस्था

- जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन का आशय
- भारतीय अर्थव्यवस्था में मानवीय संसाधन का महत्व
- भारत में जनांकिकीय प्रवृत्तियां
- जनसंख्या की संरचना
- जनसंख्या वृद्धि के कारण
- तीव्र जनसंख्या वृद्धि के भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव
- जनसंख्या नीति 2000

जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन का आशय

- सामान्यत: जनसंख्या शब्द का निर्माण- 'जन' तथा 'संख्या'- इन दो शब्दों के मेल से हुआ है। जन शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, लोग अथवा व्यक्ति, जबकि संख्या का अर्थ है गणना अथवा गिनती करना। इस आधार पर जनसंख्या का अर्थ हुआ व्यक्ति अथवा लोगों की गिनती का योग। एक देश की जनसंख्या का आशय है उस देश में निवास करने वाले लोगों (जिसमें सभी आयु के स्त्री व पुरुष सम्मिलित होते हैं) का कुल योग।
- मानवीय संसाधन शब्द मानव एवं संसाधन के योग से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है मानवीय सम्पत्ति। 'मानव संसाधन' का तात्पर्य देश विशेष की जनसंख्या, उसकी शिक्षा, कुशलता, दूरदर्शिता एवं उत्पादन से है। अर्थात् मानवीय संसाधन की गणना करते समय न केवल वहां रहने वालों की संख्या वरन् उनके गुणों पर भी विचार करना होता है। सरल शब्दों में मानवीय संसाधन, मानवीय पूंजी का ऐसा संचय है जिसको अर्थव्यवस्था का विकास करने में प्रभावी रूप से विनियोग किया जा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मानवीय संसाधन का महत्व

- प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन
- आर्थिक विकास में मानवीय संसाधन के महत्व का सर्वप्रथम विवेचन एडम स्मिथ युग के अर्थशास्त्रियों ने ही किया था। स्वयं एडम स्मिथ ने लिखा था कि ''प्रत्येक राष्ट्र का मानवीय श्रम वह कोष है जो जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है एवं अन्य सुविधाओं को जुटाता है।''
- सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० वी०के०आर०वी० राव का इस सन्दर्भ में कथन है कि ''मनुष्य न केवल उत्पादन का एक प्रमुख साधन है, बल्कि साध्य भी है।''
- फ्रेडरिक हरबिसन और चार्ल्स ए. मेयर ने भी मानवीय संसाधनों के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि ''पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सामान्यत: आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन मानवीय शक्ति की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता।''

भारत में जनांकिकीय प्रवृत्तियां

- **जनसंख्या संवृद्धि की दर:-** स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मृत्युदर में तेज गिरावट आई है (विशेषकर अकालों पर नियन्त्रण के कारण तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के कारण)। 1951-61 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की वास्तविक दर 1.96 प्रतिशत दर्ज की गयी 1961-71 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर 2.2 प्रतिशत रही जो पिछले दशक की तुलना में और भी अधिक थी ।1980 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर 2.14 प्रतिशत थी। इस प्रकार सरकार की आशा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि की दर में तेज गिरावट होगी; गलत सिद्ध हुई। 2001 की जनगणना से स्पष्ट हो गया था कि 1990 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर 1.93 प्रतिशत प्रति वर्ष रही। इसलिए भारत अभी भी जनांकिकी परिवर्तन की दूसरी अवस्था से गुजर रहा है । इसलिए जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है । 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि-दर में 1.64 प्रतिशत वार्षिक है, जिसे आगामी दशकों में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से एक सन्तोषजनक परिणाम माना जा सकता है ।
- **जन्म-दर एवं मृत्यु-दर:-**1950 से 2006 तक 56 वर्षों में जहां जन्म दर में 41.1 प्रतिशत कमी हुई है, वहां मृत्यु दर एक-तिहाई से भी कम रह गयी है । फलतः भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो गयी है । 1901 से 1921 तक 20 वर्षों में जनसंख्या लगभग स्थिर रही, क्योंकि जन्म और मृत्यु की दरें लगभग बराबर थीं। लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की दशाओं में सुधार हुआ और मलेरिया, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, हैजा, डायरिया आदि रोगों के असर में कमी हुई तो मृत्यु दर में स्थाई रूप से कमी हो गयी। पिछले सात दशकों में बाल रोगों में कमी हुई। जहां 1916-20 में बाल मृत्यु दर प्रति हजार 218 थी, वहां 2005 में यह घटकर 58 प्रति हजार रह गयी। निमोनिया, डायरिया, चेचक तथा छूत के अन्य रोगों पर नियन्त्रण से बाल मृत्यु दर नीचे आनी स्वाभाविक थी। भारत में स्त्रियों की प्रजनन आयु में भी मृत्यु दर बहुत अधिक थी। अस्पतालों की कमी और गरीबी के कारण प्रसूताओं की ठीक देखभाल न हो सकने के कारण मृत्यु दर अधिक होना स्वाभाविक था। निश्चय ही स्थिति इस समय पूरी तरह सन्तोषजनक नहीं है । लेकिन उसमें सुधार अवश्य हुआ है । इस प्रकार पिछले 56 वर्षों में चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था में जो भी सुधार हुआ है, उसका परिणाम यह है कि 2005-06 में मृत्युदर 7.5 प्रति हजार थी ।
- 1950 से 2006 तक 56 वर्षों में जन्म दर में केवल 4.1 प्रतिशत की कमी हुई है । जन्म दर को नियन्त्रित कर पाना कठिन होता है । दीर्घकाल तक परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत कोशिशें करने पर ही इस दिशा में कुछ सफलता मिल पाती है । गुरप ऑन पॉपुलेशन प्रोजैक्शन के अनुसार, वर्ष 2026 तक जनसंख्या वृद्धि की दर 0.9 हो जाने की आशा है और तब इस वर्ष जनसंख्या अनुमानतः 140 करोड़ होगी ।

जनसंख्या की संरचना

- **जनसंख्या घनत्व:-**2001 की जनगणनानुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2011 में यह बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया हैअर्थात् 2001 से 2011 के बीच के एक दशक में भारत के जनसंख्या घनत्व में 18 प्रतिशत (58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) की वृद्धि दर्ज हुई है।
- पिछले आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाय तो ज्ञात होता है कि 1951 में भारत में जनसंख्या घनत्व 117 था। इस आधार पर 2011 में इसमें 265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की भयानक वृद्धि देखने को मिलती है।
- जनसंख्या घनत्व को क्षेत्रीय आधार पर देखा जाय तो जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व मात्र 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इन क्षेत्रों को निम्नतम घनत्व वाले क्षेत्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके विपरीत केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, चण्डीगढ़, पाण्डिचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 689 से 9294 तक पाया जाता है। ये क्षेत्र सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्रों की परिधि में रखने योग्य हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा, असम, दादरा और नगर हवेली, त्रिपुरा, उड़ीसा, उत्तराखण्ड, तथा मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व मध्यम स्थिति में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 100 से 689 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य पाया जाता है।
- **ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या:-**भारत सही अर्थों में गांवों का देश है। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार 82.1 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। केवल 18.0 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। जबकि 1921 में ग्रामीण जनसंख्या 88.8 प्रतिशत और नगरीय जनसंख्या 11.2 प्रतिशत थी, किन्तु उसके बाद की अवधि में देश की औद्योगिक उन्नति होने के कारण नगरीय जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सन् 1931 में शहरी जनसंख्या 12 प्रतिशत तथा सन् 1951 में 17.3 प्रतिशत थी। सन् 1961 में 566878 गांव तथा 2699 नगर और कस्बे थे।
- सन् 1971 में ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 439 मिलियन (80.1 प्रतिशत) तथा शहरी क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 109 मिलियन (19.9 प्रतिशत) हो गयी। 1981 में गांवों की कुल जनसंख्या 524 मिलियन (76.7 प्रतिशत) तथा शहरी कुल जनसंख्या 159 मिलियन (23.3 प्रतिशत) हो गयी। इसी प्रकार 1991 में ग्रामीण कुल जनसंख्या 629 मिनियन (74.3 प्रतिशत) तथा शहरी कुल जनसंख्या 218 मिलियन (25.7 प्रतिशत) तक पहुंच गयी। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या 741 मिलियन (72.2 प्रतिशत) तथा शहरी कुल जनसंख्या 285 मिलियन (27.8 प्रतिशत) हो गयी।

जनसंख्या की संरचना

- **लिंगानुपात:-** आजादी के बाद भारतीय जनसंख्या के इतिहास में यदि 1971-81 के दशक को छोड़ दिया जाय तो 1991 तक प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात निरन्तर गिरा है। जहां 1951 में 1000 पुरुषों के मध्य 946 स्त्रियां थीं, वहीं 1971 में यह अनुपात 930 रह गया जो कि काफी चिन्ता का विषय था। परन्तु 1981 में इस अनुपात में थोड़ी वृद्धि होकर 934 तक पहुंच गया। 1991 में स्त्रियों का अनुपात पुनः गिरकर 927 रह गया। उसके बाद स्त्रियों के अनुपात में निरन्तर उठापटक जारी है। वर्ष 2001 में 1000 पुरुषों पर 933 स्त्रियां थीं किन्तु 2011 की जनगणना में यह अनुपात बढ़कर 940 हो गया।
- **जनसंख्या का व्यावसायिक वर्गीकरण:-**आर्थिक रूप से सक्रिय लोगों (15 से 59 वर्ष आयु) पर निर्भर आश्रितों (14 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक) की संख्या बहुत अधिक है। मैनपॉवर प्रोफाइल (1998) के अनुसार 1993-94 में भारत में 44.86 प्रतिशत लोग (15-59 वर्ष आयु वर्ग में) आर्थिक रूप से सक्रिय या कार्यरत थे और शेष 55.14 प्रतिशत आर्थिक रूप से निष्क्रिय थे। 1993-94 में 44.9 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और 36.3 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में श्रमशक्ति में लगे थे। लिंग के सन्दर्भ में 67.6 प्रतिशत पुरुष (15-59 आयु वर्ग के) और 32.4 प्रतिशत स्त्रियां उत्पादक कार्यों में लगे हुए थे। 15 से 59 वर्ष की आयु समूह में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की क्रियाशीलता की दर क्रमशः 73.8 प्रतिशत और 26.2 प्रतिशत है, जबकि स्त्रियों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर क्रमशः 14.9 प्रतिशत तथा 85.1 प्रतिशत है। 1993-94 में 64.6 प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) में, 14.2 प्रतिशत लोग द्वैतीयक क्षेत्र (निर्माण) में और 21.2 प्रतिशत लोग तृतीयक क्षेत्र (नौकरी) में लगे हुए हैं। पुरुषों में कार्य न करने वालों की सबसे बड़ी संख्या पूर्णकालिक छात्रों की है और स्त्रियों में घरेलू काम करने वाली स्त्रियों की। व्यावसायिक रचना की यह संरचना का प्रभाव सामाजिक स्तर पर पड़ता है, जो पुनः स्त्रियों की सामाजिक प्रस्थिति को प्रभावित करता है। श्रम शक्ति में शहरी भागीदारी दोनों (स्त्री-पुरुष) के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में काफी कम है। 0-14 वर्ष आयु समूह में विशेष रूप से क्रियाशीलता की दर दर्शाती है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ही बाल श्रम प्रथा स्त्री और पुरुष- दोनों में प्रचलित है। 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों में यह दर 5-9 वर्ष आयु समूह में 1.1 प्रतिशत और 10-14 वर्ष आयु समूह में 13.8 प्रतिशत थी तथा स्त्रियों में 5-9 वर्ष आयु समूह में 1.4 प्रतिशत और 10-14 वर्ष आयु समूह में 14.1 प्रतिशत थी। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में 10-14 वर्ष आयु समूह में यह दर 0.5 प्रतिशत और स्त्रियों में 4.5 प्रतिशत पायी गयी।
- 2001 की जनगणनानुसार श्रमशक्ति का 57.3 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र (कृषि व सम्बद्ध व्यवसायों में 56.7 प्रतिशत तथा खनन में 0.6 प्रतिशत) में लगा हुआ था। भारत में कृषि सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। परन्तु यदि 2001 में कृषि में लगी श्रमशक्ति की तुलना 1971 के आंकड़ों से की जाय तो ज्ञात होता है कि इस अवधि में कृषि के सापेक्षिक महत्व में गिरावट हुई है। 1971 में कृषि व सम्बद्ध व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का 72.1 प्रतिशत भाग लगा हुआ था जो 1991 में कम होकर 66.8 प्रतिशत तथा 2001 में इस क्षेत्र में श्रमशक्ति का 17.6 प्रतिशत भाग लगा हुआ था जबकि 1971 में 10.7 प्रतिशत। इस प्रकार 1971 से 2001 के बीच औद्योगिक क्षेत्र में संलग्न लोगों के अनुपात में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है। भारत के तृतीयक क्षेत्र में श्रम शक्ति का चौथा भाग लगा हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार तृतीयक क्षेत्र में श्रम शक्ति का 25.2 प्रतिशत भाग लगा हुआ था (इस क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार व अन्य सेवाओं को शामिल किया गया है)। इसे विपरीत 1971 में तृतीयक क्षेत्र में श्रमशक्ति का 16.7 प्रतिशत भाग लगा हुआ था। इससे संकेत मिलता है कि 1971 से 2001 के बीच तृतीयक क्षेत्र के आकार में सापेक्षिक रूप से विस्तार हुआ है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में कमी आई है।

जनसंख्या की संरचना

- **साक्षरता प्रतिशत:-**जनगणना के परिप्रेक्ष्य में उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो किसी भाषा को पढ़, लिख तथा समझ लेता हो। किसी राष्ट्र में साक्षरता की दर वहां की जनसंख्या की गुणवत्ता को दर्शाती है। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 34.45 प्रतिशत थी। 1981 में यह दर बढ़कर 43.56 प्रतिशत, 1991 में 52.21 प्रतिशत हो गयी। विकसित देशों जैसे, इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा फ्रांस की तुलना में भारत में साक्षरता प्रतिशत काफी कम रहा है, क्योंकि वहां साक्षरता का प्रतिशत 90 से 95 के मध्य है। यद्यपि भारत में साक्षरता का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है, किन्तु इस प्रतिशत वृद्धि के विपरीत गुणात्मक रूप से शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट भी आती जा रही है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 52.1 प्रतिशत था जो बढ़कर 2001 में 64.83 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया।
- 2001 में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 75.26 तथा स्त्री साक्षरता प्रतिशत 53.63 था। परन्तु इसमें पर्याप्त वृद्धि होकर 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता 82.14 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता 65.46 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गयी है।
- इस प्रकार हम देखते हैं कि आजादी के बाद जनसंख्या के साक्षरता प्रतिशत में तेजी से विस्तार हुआ है। जहां 1951 में कुल साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत था वहीं 2011 में कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत हो गयी है। अर्थात् आजादी के बाद से अब तक साक्षरता का प्रतिशत ठीक तीन गुना अधिक हो गया है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण

- जन्म एवं मृत्यु दर के बीच विस्तृत अन्तर-भारत में वार्षिक औसत जन्म दर जो 1950-51 में प्रति 1000 जनसंख्या पर 39.9 थी, 2005-06 में घटकर 23.5 प्रति 1000 व्यक्ति रह गयी। मृत्यु दर भी 1950-51 में प्रति 1000 व्यक्ति 27.4 थी 2005-06 में घटकर मात्र 7.5 प्रति 1000 व्यक्ति रह गयी। इसका अर्थ यह है कि जहां जन्म दर में मात्र 41.1 प्रतिशत की कमी हुई है, वहीं मृत्यु दर में 72.6 प्रतिशत की भारी कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या के आकार में वृद्धि होना स्वाभाविक है।
- विवाह के समय कम आयु-हमारे देश में विवाह आम बात रही है। 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में 72 प्रतिशत विवाह 15 वर्ष की आयु से पूर्व और 34 प्रतिशत 10 वर्ष की आयु से पूर्व सम्पन्न हो जाते थे। जब से स्त्री-पुरुष, दोनों में विवाह की औसत आयु में वृद्धि हुई है। यद्यपि अनुमान है कि विवाह की औसत आयु में वृद्धि हो रही है तथापि आज भी बड़ी संख्या में लड़कियों का विवाह ऐसी आयु में हो जाता है जब वे न तो सामाजिक रूप से या भावनात्मक रूप से या मनोवैज्ञानिक और आयु क्रम से ही विवाह के लिए तैयार होती हैं।
- बाल मृत्यु दर का प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्त्री की विवाह के समय आयु से है। 1995 में भारत में औसत बाल मृत्यु दर 1000 प्रति जीवित जन्म पर 74 थी- ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 80 तथा शहरी क्षेत्रों में यह दर 49 प्रति हजार थी। यदि विवाह के समय स्त्रियों की आयु के सन्दर्भ में उन्हें तीन समूहों में विभाजित करें (18 वर्ष से कम, 18-20 वर्ष, तथा 21 वर्ष से अधिक) तो ज्ञात होता है कि इन तीनों समूहों में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर (1978) में क्रमशः 141, 112, 85 थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर क्रमशः 78, 66 और 46 थी। यदि हम जनन क्षमता दर को आयु समूहों से जोड़ें (प्रति स्त्री से जन्मे बच्चों की औसत संख्या) तो पता चलता है कि जैसे-जैसे आयु समूह अधिक होता है, प्रजनन दर कम होती जाती है। यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण करना है तो स्त्रियों का विवाह (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 21-23 या 23-25 आयु समूह में किया जाए न कि 15-18 या 18-21 वर्ष आयु समूह में।

जनसंख्या वृद्धि के कारण

- अत्यधिक निरक्षरता-परिवार नियोजन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्त्रियों की शिक्षा से है और स्त्री शिक्षा विवाह के समय आयु, स्त्रियों की प्रस्थिति, उनकी प्रजनन शक्ति, बाल मृत्यु दर आदि से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है। एन.एस.एस. के द्वारा 1999 के आंकड़ों के अनुसार भारत में समूचा साक्षरता प्रतिशत 62 था, जबकि 1991 में 52.21 तथा 1981 में 43.56 प्रतिशत। 1991 में पुरुष साक्षरता प्रतिशत 64.13 था जबकि स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 39.29 था। 1999 में, यह अनुमानतः क्रमशः 73 तथा 49 प्रतिशत था। शिक्षा व्यक्ति को उदार, विशाल हृदय, नये विचारों के लिए तत्पर तथा तर्कसंगत बनाती है। यदि स्त्री और पुरुष दोनों को ही शिक्षित किया जाता है तो वे सरलता से परिवार नियोजन के तर्क को समझ जायेंगे, लेकिन उनमें से कोई एक या दोनों ही अशिक्षित होंगे तो वे अत्यधिक रूढ़िवादी एवं विवेकहीन होंगे। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि केरल में जहां कुल साक्षरता दर 89.81 प्रतिशत और स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत दर 86.91 है वहां सबसे कम जन्मदर (17.8 प्रति 1000), है जबकि राजस्थान में स्त्री साक्षरता दर 20.44 प्रतिशत के साथ देश में जन्म दर तीसरे स्थान पर सबसे ऊंची (34.6 प्रति 1000); सबसे ऊंची जन्म दर उत्तर प्रदेश में (36 प्रति 1000) है और उसके बाद मध्य प्रदेश (34.7 प्रति 1000) में है।
- परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण-धार्मिक दृष्टि से कट्टर एवं रूढ़िवादी लोग परिवार नियोजन के उपायों के उपयोग के विरुद्ध होते हैं। अधिकतर महिलाएं यह तर्क देती हैं कि वे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकतीं। कुछ स्त्रियां यह तर्क देती हैं कि स्त्रियों के जीवन का उद्देश्य ही बच्चों को जन्म देना है। इस प्रकार का दृष्टिकोण वैसे तो न्यूनाधिक सभी धर्मों में देखने को मिल जाता है, किन्तु विशेष रूप से मुसलमान महिलाओं का दृष्टिकोंण अधिक रूढ़ एवं परम्परावादी है। जिसके फलस्वरूप परिवार नियोजन कार्यक्रम आंशिक रूप से ही अपना प्रभाव दिखा पाता है। अतः जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है।
- उपचारात्मक व गर्भनिरोधक औषधियों के कारण मृत्युदर में कमी,
- अकाल और महामारी पर नियन्त्रण,
- युद्धों में कमी, तथा
- जनसंख्या का बड़ा आधार।

तीव्र जनसंख्या वृद्धि के भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव

- निम्न प्रतिव्यक्ति आय
- आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव
- पूंजी निर्माण में कमी
- अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार
- बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोत्तरी
- खाद्य समस्या, तथा
- अनार्थिक जोतों की संख्या में वृद्धि

जनसंख्या नीति 2000

- 15 फरबरी, 2000 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की थी।इस जनसंख्या नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- अ. गर्भ निरोधकों, स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना तथा आधारभूत पुनरुत्पादनीय एवं बाल स्वास्थ्य के बारे में समन्वित सेवा प्रदान करना।
- ब. कुल प्रजनन दर को कम करके आगामी दशक में 2.1 की प्रतिस्थापन दर तक लाना।
- स. स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा की जरूरतों के अनुरूप स्तर पर वर्ष 2045 तक एक स्थिर जनसंख्या को हासिल करना।

अधोसंरचना, प्राकृतिक संसाधन और भारतीय अर्थव्यवस्था

- अधो-संरचना तथा प्राकृतिक संसाधन का आशय
- अधो-संरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों का महत्व
- अधो-संरचना के विभिन्न क्षेत्र एवं आजादी के बाद उनमें हुई प्रगति
- विभिन्न प्राकृतिक संसाधन और आजादी के पश्चात् उनकी प्रगति

अधो-संरचना तथा प्राकृतिक संसाधन का आशय

- **अधो-संरचना को आधारिक संरचना, सामाजिक-उपरि पूंजी** अथवा **इन्फ्रास्ट्रक्चर** भी कहा जा सकता है। अधो-संरचना में वे सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें पूंजीगत सम्पत्ति के रूप में जाना जाता है और जिन पर सम्पूर्ण समुदाय का अधिकार होता है। सम्पूर्ण समाज इन अधो-संरचना की सुविधाओं से लाभान्वित होता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, जैसे- परिवहन सेवा (सड़क, रेलवे, वायुयान, जलीय परिवहन) शैक्षिक सेवा (स्कूल), चिकित्सकीय सेवा (अस्पताल), तथा अन्य सेवाओं (विद्युत, बैंक, डाक-तार) आदि की गणना की जाती है।
- **प्राकृतिक संसाधनों** का तात्पर्य उन उपहारों से है जो मानव को प्रकृति द्वारा (बिना कोई मूल्य चुकाए) प्रदान किये जाते हैं। इन उपहारों में भूमि, जल, वन, खनिज पदार्थ, सामुद्रिक वस्तुएं (जैसे, मछली आदि) जलवायु आदि विभिन्न प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं। ये सभी तत्व प्राकृतिक संसाधनों की परिधि में आते हैं।

अधो-संरचना एवं प्राकृतिक संसाधनों का महत्व

- किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास वहां पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर तो निर्भर करती ही है, साथ ही यह भी आवश्यक है कि उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त रीति से विदोहन करके अधो-संरचनात्मक ढांचे का विस्तार करने में सहायक होते हैं। अर्थात् प्राकृतिक संसाधन अधो-संरचना का के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध कराते हैं और उनके उपयोग से अधो-संरचनात्मक ढांचे को गति प्रदान की जाती है। ये वे मूलभूत आधार हैं जिनके द्वारा एक देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है।
- यदि कृषि और उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था का शरीर माना जाय तो परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, तथा अन्य सेवाएं उसकी धमनियां हैं, जो यहां के निवासियों की विकासपरक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही हैं।
- उद्योगों के लिए कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में जहां परिवहन सेवाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं तो देशवासियों को स्वस्थ रखने, उन्हें शिक्षित बनाने तथा उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अस्पताल, शिक्षण संस्थान तथा बैंकों जैसी अधो-संरचरनात्मक इकाइयां उपयोगी सिद्ध होती हैं।
- कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अधो-संरचना तथा प्राकृतिक संसाधन भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इनके अभाव में देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा नहीं किया जा सकता।

अधो-संरचना के विभिन्न क्षेत्र एवं आजादी के बाद उनमें हुई प्रगति

- अधो-संरचना के विभिन्न रूप हैं, यथा- परिवहन सेवा (सड़क, रेलवे, वायुयान, जलीय परिवहन); संचार सेवा (दूरभाष, डाक-तार व कम्प्यूटर), शिक्षण क्षेत्र (स्कूल), चिकित्सकीय सेवा (अस्पताल), तथा अन्य सेवाएं (विद्युत एवं बैंक)।
- 1950-51 में, भारत में रेलमार्ग की लम्बाई 53600 किलोमीटर थी जो अब 62800 किलोमीटर हो गयी है। सड़कों की लम्बाई 1950-51 में 4 लाख किलोमीटर थी जो बढ़कर अब 33 लाख किलोमीटर से भी अधिक हो गयी है।राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 66754 किलोमीटर है। यद्यपि यह कुल सड़क-जाल का केवल 2.0 प्रतिशत है, तथापि इनके माध्यम से 40 प्रतिशत यात्री आवागमन व माल ढुलाई का कार्य सम्पन्न होता है। दूसरे दर्जे पर राज्य राजमार्गों व मुख्य जिला सड़कों का स्थान है। राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्गों, जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण शहरों व कस्बों, पर्यटन केन्द्रों तथा छोटी बंदरगाहों को जोड़ने का काम करते हैं। इनकी लम्बाई लगभग 128000 किलोमीटर है। भारत में इस समय 63465 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइनें हैं। इसका एशिया के रेल परिवहन में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान है। रेलवे इस समय भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्यम है। देश में 12700 गाड़ियां, 7000 से अधिक स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती हैं। इस उद्यम में 14.11 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं। 2006-07 में रेलवे में 621.90 करोड़ यात्रियों को अपने गन्तव्य स्थानों तक पहुंचाया और 72.77 करोड़ टन माल ढोया गया। भारत में आज 12 बड़े और लगभग 200 छोटे बन्दरगाह हैं। 1951 में भारतीय जहाजों की क्षमता केवल 3.9 लाख टन थी। 31 दिसम्बर, 2005 को भारत के पास 707 जहाज थे जिनकी क्षमता 82.90 लाख टन थी। वर्तमान में भारत का विदेशी व्यापार मात्रा-अनुसार 95 प्रतिशत और मूल्य-अनुसार 70 प्रतिशत समुद्री मार्गों के माध्यम से किया जा रहा है 2007-08 के अनुसार भारत में 14 अनुसूचित एयरलाइंस तथा 65 गैर-अनुसूचित कम्पनियां हवाई परिवहन सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, इनके क्रमशः 334 तथा 201 वायुयान हैं। वर्तमान में दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद तथा बंगलोर के हवाई अड्डों का निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा आधुनिकीकरण किया गया है। इसके अलावा कोलकाता, चेन्नई तथा 35 गैर-मैट्रो व 13 अन्य हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण पर भी काम जारी है।

अधो-संरचना के विभिन्न क्षेत्र एवं आजादी के बाद उनमें हुई प्रगति

- **संचार सेवा (डाक-तार, दूरभाष, इण्टरनेट):-**वर्ष 2006-07 में भारत में 155204 डाकघर थे, जबकि दूरभाष कनेक्शनों की संख्या 2058.67 लाख थी।
- **शिक्षण क्षेत्र (स्कूल):** देश में 1921 में 1909 पूर्व माध्यमिक विद्यालय थे जो बढ़कर 1998 में 40553 हो गये। अर्थात् पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 8 दशक से कम अवधि में 21 गुना वृद्धि हुई। इसी प्रकार 1921 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 3.3 लाख थी जो बढ़कर 1998 में 6.12 लाख हो गयी। मिडिल और सीनियर स्कूलों की संख्या 1921 में 40663 थी जो बढ़कर 1998 में 1.85 लाख हो गयी। हायर सैकेण्डरी स्कूलों की संख्या 1921 में 17257 थी जो बढ़कर 1998 में 107100 हो गयीं। 1921 में कुल 45 विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित) थे जो 1998 में बढ़कर 228 हो गये ।वर्ष 2007-08 के अनुसार भारत में 767520 जूनियर बेसिक स्कूल, 274731 सीनियर बेसिक स्कूल तथा 152049 हायर सैकेण्डरी स्कूल थे ।
- **चिकित्सा क्षेत्र (अस्पताल):-**1 जनवरी 2008 को भारत में 9976 चिकित्सालय एवं औषधालय थे। इन चिकित्सालयों एवं औषधालयों में कुल 4 लाख 83 हजार शैयाओं की व्यवस्था थी ।

अधो-संरचना के विभिन्न क्षेत्र एवं आजादी के बाद उनमें हुई प्रगति

- **विद्युत:-**भारत में पहला जल विद्युत शक्तिगृह सन् 1898 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था जिसकी क्षमता 20 किलोवाट थी। इसके बाद 1903 में कर्नाटक में कावेरी नदी के जलप्रपात सिवासमुद्रम् पर 4200 किलोवाट शक्ति वाला बिजली बनाने वाला यन्त्र लगाया गया। देश में 1947 में मात्र 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता थी जो कि वर्ष 2000-01 में बढ़कर 101153.60 मेगावाट हो गयी। इसमें से 25219.55 मेगावाट पन, 71906.42 मेगावाट ताप (गैस तथा डीजल मिलाकर), 1269.63 मेगावाट पवन और 2758 मेगावाट परमाणु स्रोतों से मिलती है। 2000-01 में 4764.70 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इस वर्ष 530 अरब यूनिट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया।2006-07 में कुल 6.05 लाख गांवों में से 4.83 लाख गांवों को विद्युतीकृत कर लिया गया था। इस वर्ष विद्युत उपभोग की मात्रा 45575 करोड़ कि॰वा॰घ॰ थी।
- **बैंक-**न, 2007 तक बैंक शाखाओं की संख्या 8262 से बढ़कर 72165 हो गयी। जून 1969 में 22.2 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में थीं जो बढ़कर 2007 में 42.9 प्रतिशत तक पहुंच गयीं।

प्राकृतिक संसाधन और आजादी के पश्चात् उनकी प्रगति

- **भूमि एवं मिट्टियां**-भारत की कुल भूमि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है जो विश्व की कुल भूमि का 2.4 प्रतिशत है। इस पर विश्व की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यहां कुल भूमि का 52.7 प्रतिशत कृषि कार्यों में व 19.27 प्रतिशत भाग में वन हैं, शेष भाग में नगर, कस्बे, खनिज पदार्थ, उद्योग हैं अथवा वह भूमि उपयोग के योग्य नहीं है।
- **वन संसाधन**-भारत में कुल भूमि के 6.41 लाख वर्ग किलोमीटर भाग में वन पाए जाते हैं जो कुल भूमि का लगभग 19.27 प्रतिशत हैं।
- **जल संसाधन**-भारत में अनुमानतः 310 करोड़ एकड़ फीट जल वर्षा से प्राप्त होता है जिसका एक तिहाई भाग भाप बनकर उड़ जाता है। 45 प्रतिशत नदियों में बह जाता है, और शेष जल को भूमि सोख लेती है।

प्राकृतिक संसाधन और आजादी के पश्चात् उनकी प्रगति

- **खनिज संसाधन**-विकसित देशों की प्रगति का रहस्य इन देशों में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। आज सैकड़ों वस्तुओं के उत्पादन में खनिज पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। देश के विकास के लिए लोहा, कोयला, पैट्रोलियम अत्यन्त आवश्यक हैं जो खनिज पदार्थों से मिलते हैं। इनके अतिरिक्त सोना, चांदी, मैगनीज, तांबा, सीसा, जस्ता, अल्युमिनियम, पोटाश, अभ्रक, टिन, थोरियम व यूरेनियम का आधुनिक युग में अत्यधिक महत्व है। इनमें से अधिकांश के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, लेकिन खनिज पदार्थों के उपयोग की दृष्टि से भारत अभी भी विकसित देशों की तुलना में काफी पीछे है।
- **शक्ति के संसाधन**-आधुनिक समय में आर्थिक विकास के लिए शक्ति के संसाधनों का होना अत्यन्त आवश्यक है। इन संसाधनों में जीव, लकड़ी, गोबर, परमाणु, विद्युत, कोयला व तेल प्रमुख हैं। पैट्रोलियम के अतिरिक्त भारत सभी शक्ति-संसाधनों में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।